[श्रीमती कमला सिन्हा]

जनिक मंच से घोषणा भी की थी । यह भी उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार को भूमि और अन्य सुविधाएं देनी होंगी। बिहार सरकार ने ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा कर भारत सरकार के पास एक पत्र भी भेजा है । 8-11-93 को यह चिट्ठी जा चुकी है । लेकिन रेल मंत्री अभी भी चुपचाप बैठे हुए है। मैं सदन के माध्यम से आप से मांग करती हूं कि सरकार तत्काल बिहार सरकार के इस पत्राचार के ऊपर ध्यान देते हुए, बिहार की मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार में रेलवे जोनल कार्यालय की स्थापना करें।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : मैं भी इसकी पुरजोर ताईद करता हूं ।

Supply of F-16 fighter Air Craft to Pakistan by USA

SHRI K. R. MALKANI (Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir, efforts are afoot in Washington to sell seventy-one F-16 fighters to Pakistan. These are deep penetration, strike aircraft. They can pose a serious threat to the security of India. The position today is that India has about 50 planes of this type. Pakistan has about 30. If 71 more planes are sold to Pakistan, then Pakistan's strength in this particular respect will be double that of India. This will be a very destabilising factor and it can lead to a serious arms race. This is dangerous. The irony is that American law itself forbidg this kind of sales. Under the Pressler Amendment, any country engaged in nuclear weapons programme cannot get arms from the US. But the US Government has taken the position saying that this will toe a one time exception. Washington has been making so many exceptions, one after another, that exceptions have become the rule. All the time Washington is tilting in the direction of Pakistan. It reminds me of the leaning Tower of Pisa which leans only in one direction. In this particular context, it leans only in favour of Pakistan.

The Indian Government has been saying that this matter is only at the proposal stagey But it will not take long for it to come to the disposal stage because big business is involved here and the industrial—military complex of America will be very much interested in this business which involves more than half a billion dollars. I would, therefore suggest that the country take note of this serious threat to our defence and the Government of India should draw the immediate attention of Washington to this thing, and tell them that we in India, the Government and the people of India, will look upon a deal like this as a very unfriendly act. Thank you.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदया, मलकानी जी ने जो: प्रश्न उठाया है, मै चाहता हूं कि देश इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से पहचाने । अमेरिका के राष्ट्रपति पहले कश्मीर के बारे में, फिर पंजाब के बारे में वक्तव्य देकर भारत विरोधी एक के बाद एक इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं जिससे भारत को हानि हो रही है । वन टाइम एक्सेप्शन करके प्रेसलर ला को तोड़कर यह पाकिस्तान को 71 एफ-16 एयर क्राफ्ट मुहैया कराने जा रहे हैं । यह भारत के लिये निहायत खतरनाक बात है । उपसभाध्यक्ष महोदय, अमेरिका परमाणु अप्रसार की जो बात कर रहा है, इससे उसका खोखलापन साबित हो रहा है । अमेरिका मानवाधिकार की जो बात कर रहा है इससे उसका खोखलापन साबित हो रहा है और एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं । पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अभी उजबेगिस्तान में घोषणा की थी कि अगर भारत और पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ तो दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध हो जायेगा। इसलिये मै कहना चाहता हूं 31 मार्च की डेड लाइन—31 मार्च की तिथि पाकिस्तान ने तय की है और यह कहा है कि इस तिथि तक उनको ये प्लेन मिल जाने

चाहिये । अमेरिका उसके आगे झुक गया है और प्रेसलर ला को तोड़कर वह सीनेट में जा रहा है और 31 मार्च से पहले-पहले पाकिस्तान को 36 एयर क्राफ्ट मिल जायेंगे, यह निश्चित दिखायी दे रहा है । इसलिये हिन्दुस्तान को अमेरिका को बताना चाहिये यह अनफ्रैंडली ऐक्ट है और साथ ही साथ उसे अपनी तैयारी करनी चाहिये और उसको ऐटम बम बनाने की तरफ पूरे जोरों से जाना चाहिये । ऐटम बम जब हम बना लेंगे तो पाकिस्तान जैसे देश, चीन जैसे देश की ऐटम बम की धमकी हमारे ऊपर नहीं रहेगी । इसलिये भारत सरकार को इस संबंध में जल्दी कदम उठाना चाहिये ।

NEED TO REHABILITATE THE SIKH FAMILIES AFFECTED BY THE 1984 RIOTS.

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से गवर्नमेंट का ध्यान एक संवेदनशील मसले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, दिल्ली के 1984 के दंगों में जो लोग विस्थापित हो गये थे उनमें से 375 परिवार वापस आ गये हैं और अब दिल्ली में उनके रिहैबलीटेशन का मामला उनके सामने आ खड़ा हुआ है ।

मान्यवर, यह 375 परिवार अब अपने ही घर में बेघर हैं । बच्चों से ले कर वृद्ध और वृद्धाएँ सब फुटपाथों पर, अनाथालयों में या सड़कों पर किसी तरह गुजर-बसर कर रहे हैं । यह लोग दिल्ली के उपराज्यपाल से, माननीय मुख्य मंत्री जी से और गृह राज्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं और अपनी व्यथा को सुना चुके हैं । लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सारा प्रशासन संवेदनहीन हो गया हो । मै आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इन लोगों को जो पुरी तरह से असहाय और निराश्रित हैं, दिल्ली में फिर से रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था की जाए । इनके बच्चे जो स्कूल जाने लायक हैं, जो स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए । कम से कम हर परिवार के एक व्यक्ति को जिस लायक हो, उसको नौकरी दी जाए ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके धन्यवाद ।

Plight of the empoyees of ordnance clothing factory and Central Vehicle Depot. Avadi

SHRI MISA R. GANESAN (Tamii Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Ordnance Clothing Factory at Avadi near Madras which manufactures the proud olive-green uniforms and battle fatigues for our jawans is now facing certain problems which have ro be immediately looked into by the Ministry of Defence and the same has to be solved immediately taking into account the welfare of the employees who are working in this prestigious organisation in the South, Sir, their demands are: (a) Work load of the factory has to be increased and the management has to get sufficient raw matterials for the same. (b) ban order on appointment has to be removed and the existing vacancies have to he filled immediately. (c) The apprentices who have already completed their training and the 17 casual labourers who have been removed from service have to be given employment in the Clothing Factory. (d) As per the recommendation of the Fourth Pay Cbmmission, the existing disparity between the N.C.O.s and the I.EL-s as regards the accumulation of earned leave and encashment of leave has to be removed by issuing sufficient orders to this effect. (e) If the D.A. exceeds 50 per cent, th-3 same should be merged with the basic pay. Sir. then, the O.C.F. school has classes up to ninth standard only and the children of the O.C.F. school are then required to change their school. So, this school lias to be upgraded up to XII standard. As regards construction of residential quarters, some amount has , already been sanctioned but the construction is yet to start. So, this has to be started immediately.